गन्ने का बकाया ₹10,000 करोड़ के पार

पार्टियां बना रहीं चुनावी मुद्दा, किसान ढूंढ़ रहा विकल्प, इस बार घटेगा गन्ने का रकबा

हरवीर सिंह

बागपत-बिजनौर। बागपत जिले के बड़ौत कस्बे से करीब दो किलोमीटर दूर पुट्ठी फतेहपुर के किसान वीरेंद्र सिंह के पास 15 बीघा जमीन है और उसमें उन्होंने सिर्फ गन्ना बोया है। वीरेंद्र मलकपुर चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करते हैं। लेकिन चालू पेराई सीजन (2013-14) में गन्ने की आपूर्ति का एक भी पैसा भुगतान के रूप में उन्हें नहीं मिला है। इस मिल पर पिछले पेराई सीजन (2012-13) का भी किसानों का 61.96 करोड़ रुपये का बकाया है। ऐसे में वीरेंद्र की आर्थिक हालत का अनुमान लगाया जा सकता है। बात केवल एक मिल या एक किसान की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश गन्ना किसान भुगतान न होने के चलते आर्थिक संकट में हैं।

चालू पेराई सीजन में राज्य के किसानों ने चीनी मिलों को 24 मार्च तक 16503 करोड़ रुपये के गन्ने की आपूर्ति की है, जबकि उन्हें केवल 5,526 करोड़ रुपये का ही भुगतान मिला। यानी, चीनी मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान साढ़े दस हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सरकारी फार्मूले के मुताबिक भी निजी मिलों ने किसानों को अभी तक केवल 38.55 फीसदी मूल्य का ही भुगतान किया है। इस गणना में गन्ना मूल्य घोषित एसएपी से 20 रुपये प्रति क्विंटल कम है और इसे भुगतान के 14 दिन बाद के आधार पर बकाया माना गया है।

इस समय लोकसभा के चुनावों का माहौल चरम पर और सभी राजनीतिक दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। हर किसी का अपना तर्क है, लेकिन भुगतान का फार्मूला नहीं है। ऐसे में किसानों ने दस से बीस फीसदी तक गन्ना रकबा घटाने का फैसला ले लिया है। नतीजा अगले सीजन में चीनी उत्पादन में गिरावट और महंगी चीनी के रूप में सामने आएगा। इस संवाददाता ने बागपत

जिले के खेकड़ा से लेकर शामली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा में दर्जनों किसानों के साथ जो बातचीत की उसमें किसानों का दर्द और गन्ने का रकबा घटाने की बात सामने आई है। गन्ने केविकल्प के रूप में किसान धान और पॉपलर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, तो सभी गैर सपा दलों की भाषा एक जैसी है। बागपत से भाजपा के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह अमर उजाला से बातचीत में कहते हैं कि अकेले छपरौली विधान सभा क्षेत्र में गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने से 260 परिवारों में लड़कियों की शादी अटक गई है। मुजफ्फरनगर से भाजपा के उम्मीदवार संजीव बालियान भी इसे किसानों के लिए बड़ा संकट बताते हैं। वहीं, बिजनौर से लोक दल की उम्मीदवार अभिनेत्री जयाप्रदा भी कुछ इसी तरह किसान परिवारों में शादियां अटकने से लेकर बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरे जाने जैसे संकट की बात करती हैं। अमरोहा सीट से लोक दल उम्मीदवार राकेश टिकैत कहते हैं कि चीनी मिल मालिक दूसरे उद्योग धंधे तो चला रहे हैं, लेकिन गन्ना किसान का पैसा नहीं दे रहे हैं। टिकैत के गांव सिसौली का गन्ना जिस तितावी मिल में जाता है वहां भी इस साल की आपूर्ति के लिए केवल एक फीसदी मूल्य का ही भुगतान हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले के धनसनी गांव के किसान सुबोध कुमार कहते हैं कि अभी तक कोई भुगतान नहीं मिला है। सुबोध कहते हैं कि इस गन्ना घटाकर आधा कर देंगे। यही बात नंगला पिथौरा के किसान धर्मेंद्र कुमार और शामली के पास बुटराडा गांव के किसान विलायत खान भी कहते हैं।

वहीं, मेरठ की मवाना तहसील के बहसूमा के किसान छत्रपाल सिंह कहते हैं कि इस बार गन्ना रकबा में 20 बीघा की कटौती करेंगे और इसकी जगह धान व चारा बोएंगे। किसानों की इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बिजनौर पापलर पेड़ की खेती बहुत तेजी से गन्ने की नकदी फसल की जगह ले रही है। सहारनपुर जिले के कांसेपुर गांव के अरविंद बताते हैं कि पांच से छह साल में तैयार होने वाले इसके पेड़ों के लिए हरियाणा की यमुना नगर स्थित प्लाईवुड इंडस्ट्री एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो गई है।

अमर उजाला
28/3/14